हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084. www.rashtriyaswabhimaan.com

● वर्ष : 17 ● अंक : 55 ● मुंबई, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 ● पृष्ठ : 4 ● मूल्य 1 रुपए

जनता को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस चलाएगी अभियान

महाराष्ट्र सरकार मुंबई की जमीनों की श्वेतपत्रिका जारी करे: हर्षवर्धन सपकाल की मांग

मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा महायुती सरकार मुंबई की जमीनें पसंदीदा उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दे रही है, जबकि आम लोगों के लिए घरों की कोई ठोस नीति नहीं है। कांग्रेस ने 25 विभिन्न सामाजिक एवं श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर किफायती आवास के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। गांधी भवन, मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपकाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने म्हाडा के माध्यम से किफायती घरों की योजना शुरू की थी और मिल मजदूरों को घर देने का वादा किया था। "1 लाख 10 हजार मिल मजदूरों को घर देने का वादा था, लेकिन अब तक सिर्फ 15 हजार घर ही दिए गए हैं," उन्होंने कहा।

"मुंबई बेची जा रही है"

सपकाल ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मिलों की जमीनें उद्योगपतियों के हवाले की जा रही हैं और धारावी पुनर्विकास परियोजना को भी औने-पौने भाव में दे दिया गया है। "हवाई अड्डे से लेकर मुंबई के कई कीमती भूखंड पसंदीदा उद्योगपतियों को सौंप दिए गए हैं। जिस तरह दिल्ली में एक उद्योगपति को खड़ा किया गया, उसी तरह मुख्यमंत्री फडणवीस

ने 'कंभोज' नाम के नए उद्योगपति को मुंबई की जमीनों और एसआरए परियोजनाओं का ठेका सौंप दिया है," उन्होंने आरोप लगाया।

घर हक्क परिषद का आयोजन

किफायती आवास और जमीन नीति पर रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस ने "घर हक्क परिषद" का आयोजन रविवार, 12 अक्टूबर को दादर स्थित टिळक भवन में किया है। इस परिषद में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के साथ पूर्व सांसद कुमार केतकर, प्रदेश कांग्रेस अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख विश्वास उटगी, धर्मराज्य पक्ष के राजन राजे, इंटक के गोविंद मोहिते, सर्व श्रमिक संघ के शिशिर ढवले, आयटक के सुकुमार दामले, मिलिंद रानडे, श्रीपाद लोटलीकर और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे।

कर्जमाफी पर मंत्री का बयान "निर्लज्ज"

एक प्रश्न के उत्तर में सपकाल ने सहकार मंत्री बालासाहेब पाटिल के किसानों पर दिए बयान की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, "कर्जमाफी की लत लग गई है, यह कहना बेशर्मी की पराकाष्ठा है। जब किसान कर्ज के बोझ से टूट चुका है, तब इस तरह के बयान घाव पर नमक छिड़कने जैसे हैं। अगर मुख्यमंत्री में जरा भी शर्म है, तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें।"

स्थानीय चुनावों की तैयारी तेज

कांग्रेस ने राज्यभर में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की तैयारी भी तेज कर दी है। जिलों की समीक्षा बैठकें पूरी हो चुकी हैं और मतदाता सूची की जाँच का काम जारी है। इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिन्हें जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। गठबंधन का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा।

"लोढ़ा कबूतरखाना टॉवर बनाएं"- व्यंग्यात्मक टिप्पणी

पत्रकारों के एक अन्य प्रश्न पर सपकाल ने मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा के "कबूतरखाना" प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा, "कबूतरों की चिंता करते समय इंसानों के स्वास्थ्य पर भी विचार होना चाहिए। मंत्री लोढ़ा यदि इतने चिंतित हैं, तो 'लोढ़ा कबूतरखाना टॉवर' बनाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले धर्म, जाति और त्योहारों के मुद्दे उछालती है।

सुप्रीम कोर्ट में पटाखों पर सख्त बहस, तुषार मेहता ने दी अनोखी दलील

नई दिल्ली। दिवाली के पास आते ही पटाखों पर प्रतिबंध और परंपरा के बीच बहस फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इस बार मामला हरित पटाखों को लेकर है। सुनवाई के दौरान अदालत में हास्यपूर्ण पल तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई से मुस्कुराते हुए कहा, "हम सब भी तो बच्चे थे मीलॉर्ड!"

एनसीआर के राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि दिल्ली-एनसीआर में केवल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रमाणित होंगे और ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइटों को पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, दिवाली पर पटाखों को रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखों की अनुमति दी जाए।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या 2018 में प्रदूषण का स्तर 2024 की तुलना में कम था। इस पर मेहता ने उत्तर दिया कि कोविड के दौरान प्रदूषण थोड़ा कम था, अन्यथा प्रदूषण का स्तर लगभग वैसा ही रहा। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे साबित हो कि केवल पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई आदेश नहीं दिया है और मामले पर आगे विचार करने का संकेत दिया है। यह सुनवाई प्रदूषण नियंत्रण और परंपरागत उत्सवों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

'चल जाता है' अब नहीं चलेगा! नितिन गडकरी ने इंजीनियरों को दी सख्त

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को अभियंताओं को सख्त चेतावनी दी कि वे अपने काम में 'चल जाता है' का रवैया छोड़ दें और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करें। यह चेतावनी उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा आयोजित अखिल भारतीय फोरेंसिक सिविल इंजीनियरिंग संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में दी। गडकरी ने कहा कि सड़क और भवन निर्माण में 'प्री-कास्टिंग' (पहले ढांचा ढाल कर उसे निर्माण स्थल पर स्थापित करना) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके अनुसार, एक बार डिजाइन पैटर्न तैयार हो जाए तो निर्माण की लागत कम होगी और गुणवत्ता में सुधार होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग में। अभियंताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य घटिया गुणवत्ता का न हो क्योंकि यह उनकी कार्य की नैतिकता से जुड़ा है। उत्पादन लागत कम करने और निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है।"

गडकरी ने पुल ढहने जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि खामियों का पता लगाने के लिए ऑडिट और अनुसंधान जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण गलतियों करने वाले अभियंताओं को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने सरकारी संस्थानों और निजी ठेकेदारों से विश्व मानकों पर सफल पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। गडकरी ने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग के विकास में पूर्णता और गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।

संपादकीय

ब्रिटेन उदार वीज़ा नीति का लाभ भी दे

ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने निरंकुश टैरिफ थोपने व भारत के हितों पर कुठाराघात की नीति अख्तियार की हुई है, ब्रिटेन के साथ रक्षा व कारोबारी रिश्तों में नई शुरुआत उम्मीद जगाने वाली है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते का सिरे चढ़ना दोनों पक्षों के हित में बताया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा को नई दिल्ली और लंदन के संबंधों में एक नये सिरे से बदलाव का प्रतीक बताया जा रहा है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के प्रतीकात्मक और व्यावहारिकता की दृष्टि से गहरे निहितार्थ हैं। इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण समझौते इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हैं। जिसमें 468 मिलियन डॉलर का मिसाइल सौदा, मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये प्रतिबद्धता तथा भारत में नौ ब्रिटिश विश्वविद्यालय खोलने पर सहमत होना शामिल है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इस रिश्ते में 'एक नई ऊर्जा है', जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समन्वय चाहती है। हालांकि, मुक्त व्यापार समझौते का मूल्यांकन, इसके प्रतीकात्मक मूल्य के बजाय इसके वास्तविक आर्थिक प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के बाद भारत के लिये ब्रिटिश बाजार तक भारतीय कपड़ों, दवा और सेवाओं, विशेष रूप से आईटी और फिनटेक के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन को लेकर कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं। मसलन छोटे और मध्यम उद्यमों के सामने सस्ते ब्रिटिश आयातों से कमजोर होने या नियामक विषमताओं का सामना करने की आशंका बनी हुई है। इसमें दो राय नहीं है कि एफटीए के फलस्वरूप, ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के लिये, भारत एक अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच विकास का एक लाभप्रद अवसर और एक स्थिर अर्थव्यवस्था वाला मजबूत साझेदार का मिलना है। लेकिन इसके बावजूद मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन में भारतीय हितों की रक्षा के लिये सतर्क पहल की जरूरत भी महसूस की जा रही है।

वैसे यह भी तथ्य है कि अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा में पारस्परिक निवेश की कसौटी पर ही दोनों देशों के रिश्तों की असली परीक्षा होगी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय पेशेवरों या छात्रों के लिए वीजा मानदंडों में ढील देने से स्टारमर का स्पष्ट इनकार करना इस बहुप्रचारित साझेदारी की सार्थकता को लेकर सवाल पैदा कर सकता है। यह विडंबना ही है कि ब्रिटेन कुछ मुद्दों को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। एक ओर ब्रिटेन जहां भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बनाना और साथ ही तकनीकी सहयोग तो पाना चाहता है, लेकिन वहीं वह श्रम की गतिशीलता को लेकर सतर्क बना हुआ है, जो कि ब्रिटेन के साथ भारत के आर्थिक और शैक्षिक जुड़ाव का एक केंद्रीय मुद्दा बना रहा है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि यदि प्रतिभाओं का आदान-प्रदान एकतरफा ही रहेगा, तो पारस्परिक लाभ पर साझेदारी फल-फूल नहीं सकती। निर्विवाद रूप से यह तथ्य तार्किक है कि मुक्त व्यापार समझौते की राह अभी भी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पायी है। उल्लेखनीय है कि टैरिफ, बौद्धिक संपदा और श्रम गतिशीलता के मुद्दे पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मूल्य आधारित कूटनीति पर भारतीय प्राथमिकता को लेकर दोनों देशों में मतभेद सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि दोनों पक्षों को पुरानी कसक से प्रेरित कूटनीति से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। निर्विवाद रूप से विशेष संबंध औपनिवेशिक हैंगओवर या प्रवासी भावना पर आधारित नहीं हो सकते। इस साझेदारी का वायदा एक ऐसे सतत सहयोग के निर्माण में निहित है, जिसमें दोनों देशों के आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल सके। भारत की चिंता ब्रिटेन की भूमि से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले तत्वों पर अंकुश लगाने को लेकर भी है। निश्चय ही अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता नहीं हो सकता। हाल के दिनों में कुछ अप्रिय घटनाएं भारतीय लोकतंत्र के प्रतीकों पर प्रहार करने के रूप में सामने आ चुकी हैं।

भारत पर लगाई शर्तें और अमेरिका को दिया जवाब रेयर अर्थ के जरिये चीन ने चली नई सामरिक चाल

> हम आपको बता दें कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में रेयर अर्थ और उनसे जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर नए प्रतिबंध घोषित किए हैं। अब कोई भी विदेशी कंपनी यदि चीन से निकले इन तत्वों का उपयोग करती है तो उसे विशेष अनुमति लेनी होगी।

वैश्विक शक्ति-संतुलन अब केवल सैन्य बल या आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि उन तत्वों की उपलब्धता से भी तय हो रहा है जिन्हें "रेयर अर्थ मेटल्स" कहा जाता है। यह वह दुर्लभ खनिज हैं जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा और हरित तकनीकों की आत्मा हैं। इन्हीं पर चीन ने एक बार फिर नियंत्रण कसते हुए दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आने वाले वर्षों में वह केवल विनिर्माण महाशक्ति ही नहीं, बल्कि संसाधन-सर्वोच्चता की भूमिका भी निभाना चाहता है।हम आपको बता दें कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में रेयर अर्थ और उनसे जुड़ी तकनीकों के निर्यात पर नए प्रतिबंध घोषित किए हैं। अब कोई भी विदेशी कंपनी यदि चीन से निकले इन तत्वों का उपयोग करती है तो उसे विशेष अनुमति लेनी होगी। नये प्रतिबंधों में न केवल कच्चे खनिज शामिल हैं, बल्कि खनन, स्मेल्टिंग, रीसाइक्लिंग और मैग्नेट निर्माण तकनीक तक को नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव नई ऊँचाइयों पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उच्च-टैरिफ नीति के जवाब में चीन ने रेयर अर्थ की आपूर्ति को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है।

हम आपको बता दें कि विश्व में रेयर अर्थ का लगभग 70% खनन और 90% प्रसंस्करण (processing) चीन के नियंत्रण में है। यानी दुनिया की डिजिटल और सैन्य प्रगति की धुरी बीजिंग के हाथ में है। इसी संदर्भ में चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति के लिए जो शर्तें रखी हैं, वह केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि भूराजनैतिक प्रकृति की हैं। बीजिंग ने कहा है कि भारत को ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स तभी मिलेंगे जब वह यह सुनिश्चित करेगा कि इनका उपयोग केवल घरेलू जरूरतों के लिए होगा और ये किसी भी रूप में अमेरिका तक नहीं पहुँचेंगे।

भारतीय कंपनियों ने "एंड-यूज़र सर्टिफिकेट" (EUC) देकर यह आश्वासन दिया है कि इन मैग्नेट्स का उपयोग विनाशकारी हथियारों के निर्माण या सैन्य उत्पादन में नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन ने भारत से यह भी आश्वासन माँगा है कि वह अमेरिका को इन तत्वों तक पहुँचने से रोकने की गारंटी दे। यही वह बिंदु है जो चीन की नीति का असली उद्देश्य उजागर करता है। यानि वह भारत को अपने नियंत्रण तंत्र में बाँधना चाहता है ताकि अमेरिका–भारत तकनीकी गठजोड़ को सीमित किया जा सके।

चीन ने अपने इन कदमों को "राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा" के लिए आवश्यक बताया है। परंतु विश्लेषकों का मानना है कि यह "सुरक्षा" की आड़ में रणनीतिक संसाधनों के हथियारकरण की नीति है। यह अमेरिका की "चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल" नीति का जवाब है, जिसमें वाशिंगटन ने चीन को उच्च-स्तरीय सेमीकंडक्टर तकनीक देने पर प्रतिबंध लगाया था। अब बीजिंग उसी भाषा में जवाब दे रहा है— "यदि तुम हमें चिप्स नहीं दोगे, तो हम तुम्हें रेयर अर्थ नहीं देंगे।" साथ ही भारत जैसे देशों से वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह उसकी इस "रणनीतिक घेराबंदी" को कमजोर न करें।

देखा जाये तो भारत की दृष्टि से यह परिस्थिति दोहरी चुनौती प्रस्तुत करती है। एक ओर, भारत की ईवी (Electric Vehicle), नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इन रेयर अर्थ तत्वों पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, चीन द्वारा लगाई गई "अमेरिका-निरोधक शर्तें" भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ईवी निर्माण में प्रयुक्त मोटरों के 12 से अधिक घटकों में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आवश्यकता होती है। हल्के रेयर अर्थ के निर्यात को चीन ने फिर से शुरू कर दिया है, परंतु भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति पर नियंत्रण अब भी जारी है। इसका सीधा असर बड़े वाहनों, बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण पर पड़ रहा है।

इसके अलावा, दो-पहिया निर्माता फिलहाल हल्के मैग्नेट या फेराइट मैग्नेट का उपयोग कर रहे हैं, परंतु इससे दक्षता घट जाती है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसलिए भारत के लिए यह स्थिति एक सख्त संदेश है कि "सप्लाई चेन की स्वतंत्रता" अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है।

देखा जाये तो चीन की यह नीति केवल भारत या अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन का हिस्सा है। वह यह जताना चाहता है कि यदि पश्चिमी देश तकनीकी निर्यात पर रोक लगाएंगे, तो चीन अपने खनिज संसाधनों के वर्चस्व से जवाब देगा। चीन का यह कदम यह भी दिखाता है कि भविष्य की विश्व राजनीति 'खनिज प्रभुत्व' पर आधारित होगी। अमेरिका पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुका है। उसने अपने घरेलू रेयर अर्थ उद्योग में $520 मिलियन का निवेश किया है और MP Materials जैसी कंपनियाँ अमेरिका के भीतर "Mine-to-Magnet" आपूर्ति श्रृंखला बनाने में जुटी हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में वर्षों लगेंगे। तब तक दुनिया को चीन की शर्तें माननी ही होंगी।

देखा जाये तो भारत को इस परिदृश्य में दो रास्तों में से एक चुनना होगा। या तो चीन पर निर्भर रहकर उसके बनाए गए नियंत्रण ढाँचे को स्वीकार करे, या अपने घरेलू रेयर अर्थ खनन और प्रसंस्करण उद्योग को सशक्त बनाकर स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखला तैयार करे। मोदी सरकार के पास अब यह अवसर है कि वह "क्रिटिकल मिनरल मिशन" को उसी प्राथमिकता से आगे बढ़ाए, जिस तरह "चिप मिशन" को बढ़ाया गया है। भारत के पास अंडमान, ओडिशा और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में रेयर अर्थ के पर्याप्त भंडार हैं, आवश्यकता केवल तकनीकी निवेश और नीति-साहस की है। कुल मिलाकर देखें तो चीन की शर्तों का वास्तविक अर्थ यही है कि जो देश संसाधन-निर्भर रहेगा, वह रणनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकेगा।

सरोकार

मानव धर्म का अमर संदेश

वनवास का काल था। पांडव अपने कठिन दिनों को सह रहे थे। एक दिन जब वे सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे, तो प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जल लाने भेजा। एक-एक कर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जल लेने गए, परंतु जब उन्होंने सरोवर के पास एक अदृश्य यक्ष का स्वर सुना—"हे वीर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल पी सकोगे"—तो वे अहंकार में उत्तर दिए बिना जल पीने लगे और तत्काल भूमि पर गिर पड़े। अंत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। उन्होंने यक्ष का प्रश्न सुनकर शांत स्वर में कहा, "हे देव, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मैं जल नहीं पीऊँगा।"

तभी आरंभ हुआ वह अद्भुत संवाद, जो केवल प्रश्नोत्तर नहीं, बल्कि मानव धर्म का शाश्वत शास्त्र है।

यक्ष ने पहला प्रश्न किया—"कौन व्यक्ति शोक नहीं करता?" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—"जिसका मन नियंत्रण में होता है, वह शोक नहीं करता। जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसे न सुख विचलित करता है न दुख। नियंत्रित मन ही सच्चे आनंद का स्रोत है।"

यह उत्तर सुनकर यक्ष मुस्कुराया, क्योंकि युधिष्ठिर ने संसार के समस्त मनोविज्ञान का सार कह दिया था। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, भीतर का अस्थिर मन है। जो उसे साध लेता है, वही मृत्यु के भय और असफलताओं के तूफानों में भी अडिग रहता है।

फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा—"किसकी मित्रता कभी क्षीण नहीं होती?" युधिष्ठिर बोले—"सज्जन और संस्कारी मनुष्यों की मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वे संबंधों को लाभ-हानि या स्वार्थ से नहीं तोलते। उनका हृदय सच्चा, आचरण शुद्ध और वचन स्थायी होता है।" इस उत्तर में युधिष्ठिर ने जीवन का दूसरा धर्म बताया—निष्ठा और सच्चाई। जहाँ स्वार्थ प्रवेश कर जाता है, वहाँ मित्रता मुरझा जाती है; पर जहाँ आदर्श और मर्यादा का वास होता है, वहाँ संबंध अमर हो जाते हैं।

यक्ष का अगला प्रश्न था—"धरती से भारी और आकाश से ऊँचा क्या है?" युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा—"धरती से भारी है मां की ममता और आकाश से ऊँचा है पिता का अरमान।" यह सुनते ही आकाश तक गूंज उठी वह करुणा की ध्वनि जो केवल एक सच्चे पुत्र के हृदय से निकल सकती थी। मां की ममता वह शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है, और पिता का अरमान वह आकाश है जो उस जीवन को उड़ान देता है। मां पृथ्वी के समान धैर्यवान है, जो सब कुछ सहकर भी मुस्कराती है, और पिता आकाश की तरह विशाल, जो संतान को अपने से आगे बढ़ते देख प्रसन्न होता है।

युधिष्ठिर के इन उत्तरों से यक्ष प्रभावित हुआ। उसने पूछा—"हे धर्मराज, तुमने सत्य, मित्रता और माता-पिता का जो सम्मान किया है, उसमें मानवता का सार निहित है। बताओ, यही क्या तुम्हारा धर्म है?" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—"मानव धर्म केवल नियमों या ग्रंथों में नहीं लिखा, वह तो हर मनुष्य के अंतःकरण में अंकित है। जब मनुष्य अपने भीतर सत्य, संयम और करुणा को जागृत करता है, तभी वह सच्चा मानव बनता है। जो दूसरों के दुख को अपना समझे, जो अन्याय के सामने मौन न रहे, और जो अपने कर्तव्य का पालन बिना अहंकार के करे—वही धर्मात्मा है।" यह सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा—"हे युधिष्ठिर, तुमने मानव धर्म की सच्ची व्याख्या कर दी है। तुमने बताया कि धर्म न किसी मंदिर में है, न किसी वेद में—वह तो मानव के आचरण में है। तुम धर्म के मार्ग पर अडिग रहो।" इतना कहकर यक्ष ने उन्हें वरदान दिया और उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया।

उस दिन से लेकर आज तक युधिष्ठिर और यक्ष का यह संवाद भारतीय चिंतन का दीपस्तंभ बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल पूजा या व्रत का नाम नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और कर्तव्य का संगम है। जब मनुष्य अपने भीतर के पशु को जीतकर मानवता को अपनाता है, तभी वह इस पृथ्वी पर ईश्वर के सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है।

युधिष्ठिर का यह उत्तर केवल प्राचीन कथा नहीं, बल्कि आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक संदेश देता है—

"धर्म वही है जो सबको जोड़ता है, अहंकार वही है जो सबको तोड़ता है। जिस मनुष्य का हृदय प्रेम से भरा है, वही सच्चे अर्थों में 'मानव धर्म' का अनुयायी है।"

General से Jawan तक एक कसौटी, Indian Army ने बनाई नई Fitness Policy, साल में सबको दो बार देना होगा Combined Physical Test

भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अब से केवल जवान ही नहीं, बल्कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे शीर्ष अधिकारी भी हर वर्ष दो बार शारीरिक फिटनेस परीक्षण देंगे। यह संयुक्त शारीरिक परीक्षण (Combined Physical Test-CPT) अगले वर्ष अप्रैल से लागू होगा और इसका उद्देश्य है "फिटनेस को रैंक से ऊपर रखकर युद्धक तैयारी को नया आयाम देना।"

हम आपको बता दें कि अब तक सेना में दो अलग-अलग मानक थे। युद्धक शारीरिक दक्षता परीक्षा (BPET), 45 वर्ष तक के सैनिकों और अधिकारियों पर लागू थी। तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा (PPT) 50 वर्ष तक के अधिकारियों पर लागू थी। अब इन दोनों को मिलाकर एक ही प्रणाली बनाई गई है— CPT (Combined Physical Test)। इसमें उम्र की ऊपरी सीमा 60 वर्ष कर दी गई है। इसका अर्थ है कि अब शीर्ष तीन-सितारा अधिकारी तक इस दायरे में आएंगे।

Combined Physical Test में क्या-क्या शामिल है, इस पर गौर करें तो आपको बता दें कि 3.2 किलोमीटर दौड़ (या तेज चाल) 4.5 किलो वजन के साथ, पुश-अप्स, सिट-अप्स और रस्सी चढ़ना। हर प्रतिभागी को न्यूनतम 6 ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी पदोन्नति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, 55 वर्ष तक अधिकारी "निगरानी में" यह परीक्षण देंगे और उसके बाद 60 वर्ष तक "स्व-मूल्यांकन" के आधार पर फिटनेस की पुष्टि करेंगे।

देखा जाये तो सेना का यह फैसला केवल शारीरिक कसौटी का विस्तार नहीं, बल्कि नेतृत्व दर्शन में बदलाव का संकेत है। आधुनिक युद्ध का स्वरूप भले तकनीक-प्रधान हो गया हो, परंतु "मानवीय तत्व" उसकी आत्मा बना हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी जो स्वयं मैदान में शारीरिक रूप से सक्षम है, वही अपने जवानों में आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना जगा सकता है। यह निर्णय सेना के उस सिद्धांत को पुनः पुष्ट करता है कि "नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण बनकर नेतृत्व करना है।" सेना के दस्तावेज़ में भी यही भाव है कि कमांडर को "हर समय अग्रिम मोर्चे पर टीम का नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए।" अर्थात, यह कदम सेना के नेतृत्व में शारीरिक विश्वसनीयता और नैतिक अधिकार दोनों को पुनर्स्थापित करता है।

देखा जाये तो आज के युद्धक्षेत्र का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहा। यह अब केवल "शक्ति के टकराव" का नहीं, बल्कि "सहनशक्ति और तत्परता" का युद्ध है। हाइब्रिड वॉरफेयर, मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस, काउंटर-इंसर्जेंसी और सीमित संसाधनों में त्वरित प्रतिक्रिया, इन सबके लिए सैनिक का शारीरिक और मानसिक रूप से उच्चतम स्तर पर रहना आवश्यक है। डिजिटलाइजेशन और ड्रोन-आधारित युद्धक प्रणालियों के बावजूद, 'मानव शरीर' ही हर सैन्य अभियान का केंद्रबिंदु है। इसलिए सेना का यह फैसला केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक कदम है।

सेना दस्तावेज़ के शब्दों पर गौर करें तो इसमें कहा गया है, "ताकत, सहनशक्ति और चपलता युद्ध की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।" "चुस्त-दुरुस्त सैनिक अपनी यूनिट के लिए अधिक सक्षम, विश्वसनीय और प्रभावी भूमिका में होता है।" यह बात केवल जवान पर नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व पर भी समान रूप से लागू होती है।

सेना ने दो अलग-अलग प्रणालियों को समाप्त कर एकीकृत CPT लागू किया है तो इसका अर्थ है संचालनात्मक एकरूपता (Operational Simplification)। अब रैंक, आयु या लिंग के अनुसार अलग-अलग मानक नहीं होंगे, बल्कि एक समन्वित तालिका होगी, जो सभी को समान मापदंडों पर परखेगी। इससे दो प्रमुख लाभ होंगे। पहला- अब फिटनेस का मूल्यांकन स्पष्ट, तुलनीय और निष्पक्ष होगा। दूसरा- अलग-अलग परीक्षणों की जगह एकीकृत प्रणाली अपनाने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। यह सुधार केवल "शारीरिक फिटनेस" नहीं बल्कि "संस्थागत फिटनेस" का भी प्रतीक है, यानी एक ऐसी सेना जो खुद को बदलते समय के अनुसार ढालने की क्षमता रखती है।

हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय सेना ने हाल के वर्षों में कई सुधार आरंभ किए हैं। अग्निपथ योजना के ज़रिए जवानों की औसत आयु घटाकर युवा प्रोफ़ाइल बनाई गई, थियेटर कमांड संरचना की दिशा में कदम बढ़ाए गए और अब यह फिटनेस का आधुनिकीकरण उसी प्रक्रिया का अगला चरण है। इससे यह संदेश जाता है कि भारतीय सेना न केवल हथियारों से, बल्कि मानवीय गुणवत्ता और आत्म-अनुशासन से भी युद्धक क्षमता बढ़ा रही है। यह कदम सैन्य नैतिकता में भी एक नए युग की शुरुआत है— जहाँ सीनियरिटी से ज़्यादा फिटनेस और पद से ज़्यादा उदाहरण मायने रखेगा।

सेना का यह निर्णय एक संदेश और संकल्प दोनों है। संदेश यह कि हर रैंक पर सैनिक वही है जो मैदान में सक्रिय रह सके और संकल्प यह कि सेना केवल युद्ध नहीं लड़ती, वह राष्ट्र को आत्मबल और अनुशासन की प्रेरणा भी देती है।

नजरिया

व्रत के दिन सुई-धागा मत चलाओ – इसके पीछे छिपा है गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक विज्ञान

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

भारतीय संस्कृति में हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। आज करवाचौथ के शुभ अवसर पर जब देशभर की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो उनके आचरण से जुड़े कई नियम और निषेध सामने आते हैं। उन्हीं में से एक नियम है कि व्रत के दिन सुई-धागा नहीं चलाना चाहिए। यह बात हर दादी-नानी, मां और बड़ी-बुजुर्ग औरतें अपनी अगली पीढ़ी को समझाती आई हैं। लेकिन क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई दार्शनिक और ऊर्जात्मक कारण भी है?

करवाचौथ का व्रत केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह एक साधना है जिसमें स्त्री अपने मन, शरीर और आत्मा को संयमित रखती है। वह पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखती है, न केवल अपने पति के दीर्घायु के लिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, श्रद्धा और भक्ति को स्थिर करने के लिए भी। इस दिन का हर नियम ऊर्जा के संतुलन और ध्यान की गहराई से जुड़ा होता है।

सुई-धागे का काम देखने में सामान्य लगता है, पर यह बहुत सूक्ष्म और केंद्रित मानसिक ऊर्जा मांगने वाला कार्य है। जब कोई व्यक्ति सुई में धागा पिरोता है या कपड़ा सीता है, तो उसका ध्यान भौतिक स्तर पर केंद्रित हो जाता है। व्रत के दिन व्यक्ति को सांसारिक कार्यों से मन हटाकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए, ताकि उसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी बनी रहे। यही कारण है कि इस दिन ऐसे कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है जो मन को बाहरी संसार में बांध दें।

वास्तव में सुई और धागा प्रतीक हैं "बंधन" और "कर्म" के। सुई जोड़ती है, धागा बांधता है, और सिलाई का अर्थ है दो वस्तुओं को एक सूत्र में पिरोना। जबकि व्रत का भाव है — मुक्ति, समर्पण और ईश्वर के प्रति एकनिष्ठता। जब स्त्री व्रत रखती है, तो वह अपने सांसारिक कर्मबंधनों से एक दिन के लिए विरक्ति लेकर भगवान से एकत्व का अनुभव करती है। इसीलिए उसे कहा गया — आज कुछ मत सिलना, क्योंकि यह दिन कुछ जोड़ने का नहीं, बल्कि सब छोड़कर ईश्वर में विलीन होने का है।

तांत्रिक और योगशास्त्र की दृष्टि से भी इसका गहरा अर्थ है। जब व्यक्ति उपवास करता है, तो उसके भीतर की प्राणशक्ति अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। उसका शरीर सूक्ष्म ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। इस अवस्था में किसी नुकीली या धातु की वस्तु से कार्य करना ऊर्जा प्रवाह में व्यवधान डाल सकता है। सुई का स्पर्श नाड़ियों के ऊर्जावान संतुलन को क्षीण कर सकता है, जिससे मन अशांत हो जाता है। प्राचीन काल में जब स्त्रियां ऊर्जा-संतुलन और ध्यान में दक्ष थीं, तब यह अनुभवजन्य सत्य के रूप में जाना गया था।

कुछ परंपराओं में तो यह भी कहा गया है कि व्रत के दिन सुई या कैंची का उपयोग करना अशुभ होता है, क्योंकि ये वस्तुएं "छेदन" या "विभाजन" का प्रतीक हैं। व्रत का दिन प्रेम, एकता और साधना का होता है, ऐसे में विभाजन या काटने-जोड़ने का प्रतीक कार्य ऊर्जा के स्तर पर नकारात्मक कंपन पैदा करता है। यही कारण है कि दादी-नानी अपने अनुभव से कहती थीं — आज सुई मत चलाना, वरना पूजा का पुण्य घट जाएगा।

कहते हैं एक बार एक गांव में सावित्री नाम की स्त्री करवाचौथ का व्रत कर रही थी। दिनभर उपवास रखने के बाद वह शाम को चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कपड़े का किनारा फट गया। उसने सोचा, "थोड़ी देर ही तो है, सिल लेती हूं।" जैसे ही उसने सुई उठाई, उसका हाथ हल्का-सा चुभ गया और खून निकल आया। उसी समय आंगन में रखा दीपक बुझ गया। सावित्री घबरा गई और तुरंत सुई रख दी। बुजुर्ग सास ने कहा, "बिटिया, व्रत का दिन साधना का होता है, इस दिन शरीर में जो ऊर्जा होती है वह बहुत पवित्र और कोमल होती है, उसमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

संक्षिप्त समाचार

भिवंडी मनपा में शुरू हुई 'एक खिड़की योजना', अब सभी व्यावसायिक परवाने एक ही स्थान से मिलेंगे

भिवंडी । भिवंडी मनपा प्रशासन ने शहर के व्यवसायियों और औद्योगिक इकाइयों की सुविधा के लिए 'एक खिड़की योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत अब शहर की सभी व्यावसायिक संस्थाएँ, कारखाने और गोदाम विभिन्न परवाने और ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) केवल एक विभाग से प्राप्त कर सकेंगे।

मनपा के जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी ने बताया कि महाराष्ट्र मनपा अधिनियम, 1949 के तहत महानगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत हर व्यावसायिक इकाई के लिए व्यवसाय परवाना और ना हरकत प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए यह योजना लागू की गई है। योजना के नोडल अधिकारी के रूप में उपआयुक्त (परवाना) नियुक्त किए गए हैं।

आयुक्त एवं प्रशासक अनमोल सागर ने निर्देश दिए हैं कि परवाना विभाग प्रमुख, नोडल अधिकारी के अधीन रहकर उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कारखानों और गोदामों का सर्वेक्षण करें, जिन्होंने अभी तक ना हरकत प्रमाणपत्र नहीं लिया है या जिनके पास वैध परवाना नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस योजना के तहत अब परवाना, पर्यावरण, अग्निशमन, और मालमत्ता कर से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन परवाना विभाग में ही स्वीकार किए जाएंगे। विभाग के कर्मचारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से बकाया मालमत्ता कर, पर्यावरण और अग्निशमन शुल्क, तथा परवाना फीस की वसूली एक साथ करेंगे। आयुक्त अनमोल सागर ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने सभी आवेदन 'एक खिड़की योजना' के तहत परवाना विभाग में जमा करें, ताकि निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार उन्हें परवाना प्रमाणपत्र प्राप्त हो सके।

भिवंडी के गोदामों में बढ़ रही आगजनी, विद्युत सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य

भिवंडी। भिवंडी के गोदाम बाहुल्य इलाकों में आगजनी की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए विद्युत विभाग सतर्क हो गया है। आग लगने के अधिकांश मामले शॉर्टसर्किट और पुरानी केबलिंग के कारण होते हैं, जबकि गोदाम मालिक विद्युत सुरक्षा ऑडिट नहीं कराते। विशेष रूप से अंजुरफाटा, रहनाल, पूर्णा, काल्हेर, दपोड़ा, सावडे, लोनाड, सोनादेवी लॉजिस्टिक्स और एमआईडीसी क्षेत्र के औद्योगिक गोदाम खतरे में हैं। विद्युत निरीक्षक ने बताया कि नियमित निरीक्षण और फायर सेफ्टी उपकरणों की अनुपस्थिति पूरे क्षेत्र को संभावित हॉट स्पॉट बना देती है। इसलिए सभी गोदामों में वार्षिक विद्युत सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। बिना मान्य विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिजली कनेक्शन या कार्य अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने वाले गोदामों के खिलाफ जुर्माना और बिजली आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई होगी। विद्युत विभाग ने गोदामों को नोटिस भेजकर आवश्यक सुधार की चेतावनी दी है, ताकि आगजनी जैसी घटनाओं को रोका जा सके और मजदूरों, नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत की वृद्धि

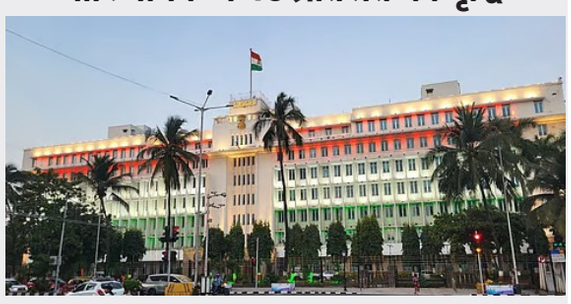

मुंबई। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य भर के लगभग 50,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस फैसले पर संविदा कर्मचारियों ने खुशी जताई और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर को बधाई दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की नियुक्ति विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु की गई है। पिछले कुछ समय से कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। सरकार का यह निर्णय जून 2025 के देय पारिश्रमिक के आधार पर लागू किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार उनकी अन्य शेष मांगों के प्रति भी सकारात्मक है। इन मांगों में शामिल हैं –

दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखना,

एनएचएम कर्मचारियों को ईएसआईएस के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना,

गंभीर बीमारी, विकलांगता या मृत्यु जैसी स्थिति में आर्थिक सहायता देना,

एनएचएम कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना,

अति दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता प्रदान करना,

संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में अंतर को समाप्त करना।

वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारी इस वेतन वृद्धि का लाभ उठाएंगे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि शेष मांगों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में मराठी भाषा और राज्यगान का गायन अनिवार्य करने का प्रस्ताव, शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने दिए निर्देश

मुंबई। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने सुझाव दिया है कि राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा का अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य किया जाए और छात्रों से राज्यगान का गायन भी अनिवार्य कराया जाए। मंत्री ने यह बात सभी शिक्षा बोर्डों के समन्वयकों, प्राचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक परामर्श बैठक में रखी।

उन्होंने कहा कि आईसीएसई, सीबीएसई और कैम्ब्रिज बोर्ड से जुड़े स्कूलों के विद्यार्थियों की दसवीं कक्षा की मार्कशीट में मराठी भाषा भी शामिल की जानी चाहिए। इसके लिए संबंधित बोर्डों के साथ पत्राचार किया जाएगा। साथ ही, राज्य बोर्ड की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और कार्यों से संबंधित पाठ्यक्रम भी आईसीएसई बोर्ड की पुस्तकों में शामिल किए जाने चाहिए।

इसके अलावा मंत्री ने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के स्कूलों में मानविकी विषयों में महाराष्ट्र के इतिहास के शिक्षण पर भी विचार किया जाना चाहिए। दिव्यांग और कम सीखने की क्षमता वाले विद्यार्थियों को भी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित हो सके। शिक्षा के

अधिकार अधिनियम के तहत अन्य बोर्ड के स्कूलों में लागू की जाने वाली प्रवेश नीतियों और विभिन्न पहलों को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

मंत्री भुसे ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का संचार किया जाना चाहिए। इसके तहत 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसी पहल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अच्छी सुविधाओं वाले अन्य बोर्ड के स्कूलों को भी मराठी माध्यम के स्कूलों का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे शिक्षा का स्तर समान और सुदृढ़ बनाया जा सके।

बैठक में विभिन्न बोर्डों के समन्वयकों और प्रधानाचार्यों ने अपने विद्यालयों में संचालित विभिन्न गतिविधियों, सीखने-सिखाने के प्रयोगों और मूल्यांकन विधियों के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने इन पहलों और सुझावों को लागू करने की दिशा में कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

भिवंडी मनपा क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति बंद, मुख्य पाइपलाइन का स्थानांतरण

भिवंडी । भिवंडी मनपा क्षेत्र के कई हिस्सों में रविवार को पूरे 24 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। मनपा जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने बताया कि भिवंडी शहर में पानी सप्लाई करने वाली मुख्य पाइपलाइन को मानसरोवर इलाके में स्थानांतरित किया जाएगा। इस कार्य के कारण शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 सुबह 9 बजे से रविवार, 12 अक्टूबर 2025 सुबह 9 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने नागरिकों से इस दौरान पानी का संभलकर उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे बताया कि पाइपलाइन स्थानांतरण के अगले दिन पानी कम प्रेशर में या दबाव कम होने के साथ सप्लाई किया जाएगा।

पानी सप्लाई नहीं होने वाले क्षेत्र

पद्मानगर, गायत्रीनगर, रामनगर, नवजीवन कॉलनी, बीएनएन

कॉलेज रोड, पटेल कंपाउंड गल्ली नं. 1,2,3, भैयासाहेब आंबेडकर नगर, न्युप्रकाश नगर, माधवनगर, सोमनगर, विठ्ठलनगर, गंगाराम वाडी, लकडाचाळ, न्यू टावरे कंपाउंड, दुधबावडी, हाफिजनगर, आलमगीर वीडियो परिसर, न्यू इंस्लामाबाद, आझमीनगर, खालीक शेठ चाळ दिवानशाह, हांडी कंपाउंड समरुबाग, इदगाह रोड, कारीवली रोड, दर्गा रोड, मोमिन बाग, कोतवालशाह, मुर्तुजा कंपाउंड, धोबी तलाव, बाबू चुनिवाला बिल्डिंग, टावरे वाडी, चारचाळी, हमालवाडा, तंडेल मोहल्ला, बंदर मोहल्ला, सौदार मोहल्ला, मुकरी शाह, सुतारआळी, भोईवाडा, भुसार मोहल्ला, ब्राम्हणआळी, कासारआळी, पोस्ट ऑफिस के पास, बाजारपेठ, हफसन आळी, जैतुनपूरा, कापतलाव, समदशेठ बगीचा, बंगालपूरा, धोबी मोहल्ला, सोनापूर, तेली मोहल्ला, कॅसरबाग, ठाणारोड, बोबडे मोहल्ला, गौरीपाडा, भुसार मोहल्ला, खजुरपूरा, नाचन कंपाउंड, समदनगर, कणेरी, पायल टॉकीज के पास, अजंठा कंपाउंड 1 व 2, धामनकर नाका, वॉटर सप्लाय कॉलनी, ठाणगेआळी, तीनबत्ती, फैजान कंपाउंड, मेहता कंपाउंड, रोशनबाग, देऊनगर टावरे कंपाउंड, निजामपूरा, विठ्ठलनगर चींचेच्या झाडा के पास, ग्लोबल कॉम्प्लेक्स, खालीक शेठ कंपाउंड रोशनबाग। इस दौरान जनता को पानी का सजग और विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी गई है।

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए शिवसेना महिला आघाडी पूरी तरह तैयार

मुंबई। आगामी मुंबई महानगरपालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए, शिवसेना महिला आघाडी ने महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर विशेष रणनीति तैयार की है। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक मतदान किया था। कुल 55.92% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 55.07% था। मुंबई के 24 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक दर्ज हुआ।

महामंगलागौर स्पर्धा में महिलाओं ने दिखाई प्रतिभा

महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके उत्साह को बढ़ावा देने के लिए शिवसेना महिला आघाडी ने कई पहल की हैं। इसी कड़ी में "महामंगलागौर स्पर्धा" हाल ही में मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 60,000 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 60 अक्टूबर 2025 को भारती विद्या भवन में किया गया, जिसमें गृहराज्य मंत्री योगेश कदम मुख्य अतिथि थे।

मागाठाणे की कलादर्पण टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान भायखला

की शिवकन्या टीम और तीसरा स्थान चेंबूर की चंद्रकोर टीम को मिला।

महिलाओं के लिए अन्य विशेष कार्यक्रम

राज्य में लाडकी बहिण योजना की सफलता के बाद शिवसेना ने महिलाओं के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। शिवसेना उपनेता शीतल म्हात्रे ने कहा कि महिला आघाडी शिवसेना का अभिन्न हिस्सा है और पार्टी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि आने वाले महानगरपालिका चुनाव में लाड़की बहनें विरोधियों को करारा जवाब देंगी।

"उत्सव मुंबईचा" प्रतियोगिता में गणेश मंडलों ने भाग लिया

महामंगलागौर प्रतियोगिता के साथ ही "उत्सव मुंबईचा" सार्वजनिक गणेशोत्सव सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 450 गणेश मंडलों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 50 मंडलों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया। हनुमान सेवा मंडल ने पहला पुरस्कार जीता। निकदवरी लेन सार्वजनिक मंडल (गिरगांवचा राजा) और ताडदेव पुलिस कॉलोनी सार्वजनिक मंडल (वर्दीचा राजा) को संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार, जबकि भांडुप के कोकण मित्र मंडल और शिवाजी पार्क (हाउस) को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया।

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन शिवसेना नेता मीनाताई कांबळी, उपनेता एवं प्रवक्ता शीतल म्हात्रे, सचिव एवं शिव चित्रपट सेना अध्यक्ष सुशांत शेलार के मार्गदर्शन में किया गया।

महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव

शिवसेना महिला आघाडी का उद्देश्य महिलाओं को केवल राजनीति में भागीदारी का मंच देना ही नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। आगामी महानगरपालिका चुनाव में महिला मतदाता शिवसेना के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं, और पार्टी इसे ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यक्रम और अभियान चला रही है।

भिवंडी मनपा में फिर चली 'तबादला एक्सप्रेस', 13 अधिकारियों का स्थानांतरण

भिवंडी । भिवंडी मनपा प्रशासन ने एक बार फिर कर्मचारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें 13 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम समिर जवरे, मिलिंद पलसुले और निहाला इरफान पटेल के हैं।

आदेश के अनुसार, समिर जवरे, जो मूल रूप से लिपिक पद पर कार्यरत थे, को शहर विकास विभाग का प्रभारी कार्यालय अधीक्षक और विभाग प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह विभाग अवैध बांधकाम, जर्जर इमारतों के निष्कासन और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यह पद सामान्यतः "बिल्डिंग कम इंस्पेक्टर" डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित होता है, इस बार एक लिपिक को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व प्रभारी अधिकारी अरविंद घुगरे अब केवल अतिक्रमण मुक्त पथक के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहेंगे।

मिलिंद पलसुले को क्रीड़ा विभाग

का प्रभारी और समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अन्य तबादले इस प्रकार हैं:

- विनोद सकपाल – प्रभारी उपनिबंधक (जन्म-मृत्यु नोंदणी)
- सुनील चौहान – प्रभाग समिति 5 का प्रभारी
- निहाला इरफान पटेल – दूरध्वनी विभाग का प्रभारी
- आम्रपाली सोरटे – जन्म-मृत्यु नोंदणी लिपिक
- विश्वास वाघे – स्थापना विभाग लिपिक
- अलका मटाले – दूरध्वनी विभाग लिपिक
- प्रवीण गोडे – निवडणूक विभाग लिपिक का अतिरिक्त चार्ज
- अकबर शेख – प्रभाग समिति 1 प्रभारी लिपिक
- स्वप्निल गायकवाड़ – कर मूल्यांकन विभाग प्रभारी सिपाही
- अभिषेक घोष्टेकर – भविष्य निर्वाह निधि विभाग सिपाही

सभी तबादले भिवंडी मनपा प्रशासक एवं आयुक्त अनमोल सागर के आदेश पर, उपायुक्त (मुख्यालय) विक्रम दराडे के हस्ताक्षर से किए गए हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

समाजसेवी पन्नालाल मिश्रा के जन्मदिवस पर वी.एम फाउंडेशन ने आयोजित किया प्रेरणादायी रक्तदान शिविर

राष्ट्रीय स्वाभिमान। प्रेम चौबे

नालासोपारा । नालासोपारा-वसई विरार के सम्मानित उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाजसेवी पन्नालाल मिश्रा ने अपने 65वें जन्मदिवस पर मानवता और समाजसेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया। इस अवसर पर ओसवाल नगरी, सरस्वती हाईट्स, शॉप नं.1 में वी.एम फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रेरणादायी रक्तदान शिविर ने सेवा और करुणा का जीवंत उत्सव पेश किया। शिविर में 100 से अधिक रक्तदाताओं ने भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का परिचय दिया। सरला ब्लड बैंक ने तकनीकी सहयोग और सुव्यवस्था प्रदान की।

कार्यक्रम के आयोजक और वी.एम फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत मिश्रा ने कहा कि रक्तदान केवल जीवनदान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का माध्यम है। मिश्रा परिवार ने

यह सिद्ध किया कि व्यक्तिगत उत्सव भी समाजहित में परिवर्तित हो सकते हैं। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। सभी रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र, उपहार, स्टील वाटर बोतल और टिफिन बॉक्स देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह बढ़ा और अन्य लोगों को प्रेरणा मिली।

कार्यक्रम में पूर्व नगरसेवक, सभापति, समाजसेवी और उद्योगपति सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और पन्नालाल मिश्रा के प्रयास की सराहना की। शिविर को सफल बनाने में वीरेंद्र मिश्रा, लवलेश पांडे, मुकेश त्रिपाठी, राजीव सिंह, प्रवीण पांडेय, राकेश सिंह, संजय मीणा, सत्यप्रकाश सिंह, राहुल मिश्रा, राजेश पाठक, आंसू मिश्रा, आकाश पांडेय, विरामन पांडेय, अमन तिवारी, विवेक तिवारी, मनोज यादव, परशु नेगी, सागर पांडेय, विमल पांडे और विनीत सिंह का विशेष योगदान रहा।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल जीवन की ज़िम्मेदारी: डॉ. कैलाश पवार

ठाणे । 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' के अवसर पर ठाणे सिविल अस्पताल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिला शल्य चिकित्सक डॉ. कैलाश पवार ने मानसिक स्वास्थ्य को जीवन का एक अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि इसका ध्यान रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

डॉ. पवार ने कहा कि शारीरिक बीमारी में समाज तुरंत मदद के लिए आगे आता है, लेकिन मानसिक कष्ट के मामले में झिझक और कलंक के कारण लोग सहायता नहीं करते। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं होनी

चाहिए, बल्कि स्कूलों, कार्यस्थलों और ग्राम स्तर पर परामर्श केंद्र होने चाहिए। समय पर मानसिक तनाव, अवसाद या आत्महत्या की प्रवृत्ति पर ध्यान देने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉ. धीरज महांगड़े, निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मृणाली राहुड़, मनोचिकित्सक डॉ. विजय तेली, डॉ. अर्चना पवार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस वर्ष का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय है, "आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता"। ठाणे जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसी के अनुरूप एक महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस दौरान जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, पुलिस थानों, अग्निशमन दस्तों और एनडीआरएफ टीमों में मानसिक स्वास्थ्य सत्र, कार्यशालाएँ, तनाव प्रबंधन कक्षाएं, निबंध प्रतियोगिताएँ और जागरूकता रैलियाँ आयोजित की जाएँगी।

अस्पताल के मनोचिकित्सकों ने कार्यक्रम के दौरान मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श सत्र भी आयोजित किए। ठाणे जिला स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और मानसिक स्वास्थ्य को समाज की शक्ति बनाने में योगदान दें।

किसानों को कर्जमाफी की लत लग गई हैफडणवीस के मंत्री का विवादित बयान, महाराष्ट्र में सियासी बवाल

मुंबई। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने हाल ही में अपनी कथित टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग कर्जमाफी के प्रति लालायित रहते हैं। पाटिल ने यह भी स्वीकार किया कि राजनेता चुनाव जीतने के लिए वादे करते हैं।

मंत्री पाटिल ने यह टिप्पणी एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की। उनके भाषण के अंश क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर प्रसारित हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय और स्थान स्पष्ट नहीं है। उनके इस बयान पर सत्तारूढ़ सहयोगियों सहित कई राजनीतिक हलकों से कड़ी आलोचना हुई। भाजपा नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसी को भी कर्जमाफी के मुद्दे पर हल्के-फुल्के बयान नहीं देने चाहिए।

उन्होंने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की टिप्पणियां असंवेदनशील मानी जा रही हैं।

पाटिल ने भाषण में कहा कि लोग कर्जमाफी के प्रति लालायित रहते हैं। हम (नेता) चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए चुनाव के दौरान आश्वासन देते हैं। लेकिन यह जनता को तय करना है कि वे वास्तव में क्या मांगना चाहते हैं। चुनाव के दौरान, एक नेता एक गांव में आए, और लोगों ने कहा – 'जो भी हमारे गांव में नदी लाएगा, हम उसे वोट देंगे।' अब, क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे क्या मांग रहे हैं? तब नेता ने कहा, 'ठीक है, हम आपको एक नदी भी देंगे।' इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को सोच-समझकर तय करना चाहिए कि वे क्या मांग रहे हैं। पाटिल ने स्पष्ट किया कि नेता वादे इसलिए करते हैं क्योंकि चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन इन बातों पर जनता को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राजस्व मंत्री बावनकुले की आपत्ति

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि किसी को भी ऋण माफी के मुद्दे पर हल्की-फुल्की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन के घोषणापत्र में पात्र किसानों के लिए ऋण माफी का स्पष्ट उल्लेख था। जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कई किसान वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन अपना पूरा ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail.com

04 मुंबई, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 महाराष्ट्र

epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

किसानों के लिए मोदी विशेष पैकेज दें, फडणवीस द्वारा दिया गया पैकेज एक छलावा है: हर्षवर्धन सपकाल

नाशिक। महाराष्ट्र में अतिवृष्टि के कारण तबाह हुए किसानों की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि भाजपा महायुति सरकार ने किसानों को धोखा दिया है और घोषित पैकेज पूरी तरह छलावा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए।

"किसानों के साथ क्रूर मज़ाक"

सपकाल ने कहा, राज्य सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है, उसमें फसल बीमा और बिजली गिरने से हुई मृत्यु की सहायता को भी शामिल किया गया है। यह

किसानों के साथ क्रूर मज़ाक है। उन्होंने मांग की कि सरकार 'ओला सूखा' घोषित कर प्रति हेक्टेयर रु 50,000 की सहायता, भूमि बहने पर रु 5 लाख मुआवज़ा, और कर्जमाफी की घोषणा करे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी मुंबई आए, लेकिन किसानों के लिए एक शब्द तक नहीं बोले। उन्होंने केवल अपने मित्र के हवाईअड्डे का उद्घाटन किया, जबकि राज्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। यह महाराष्ट्र का अपमान है।

नाशिक में उत्तर महाराष्ट्र विभाग की बैठक

उत्तर महाराष्ट्र के जिलों की समीक्षा बैठक नाशिक में सपकाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनावों की रणनीति और संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात, सांसद शोभा बच्छाव, एआईसीसी सचिव बी.एम. संदीप, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, प्रदेश महासचिव गुरबिंदर सिंह बच्छर, प्रवक्ता सचिन सावंत, नाशिक ग्रामीण अध्यक्ष शिरीष कोतवाल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे।

"क्या महाराष्ट्र को तालिबान बनाना है?"

कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी सपकाल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, "राज्य में 9 महीनों में 44 हत्याएं हुई हैं, ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। यह स्थिति देखकर लगता है कि क्या महाराष्ट्र को तालिबान बनाना है? राज्य में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है, और गृहराज्यमंत्री के पारिवारिक नाम से डांस बार चलना तथा गुंडों को हथियार लाइसेंस देना जैसी घटनाएँ शर्मनाक हैं। सपकाल ने मांग की कि वादग्रस्त गृह राज्य मंत्री योगेश कदम को तत्काल बर्खास्त किया जाए।

न्यायाधीश पर हमला "मनुवादी कृत्य"

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई पर अदालत में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए सपकाल ने कहा, "हमलावर का पूरा नाम जानबूझकर छिपाया जा रहा है। यह मनुवादियों की करतूत है। डोंबिवली में कांग्रेस कार्यकर्ता पर जातिवाचक अत्याचार हुआ था, अब यह उसी की अगली कड़ी है। अगर अब भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो यह प्रवृत्ति पूरे राज्य में फैल जाएगी।"

कांग्रेस में नई नियुक्तियाँ

बैठक में प्रो. ज्ञानेश्वर गायकवाड़ को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस मेडिकल सेल का राज्य प्रमुख (विदर्भ छोड़कर) और डॉ. अभ्युदय मेघे को विदर्भ प्रमुख नियुक्त किया गया। इस अवसर पर हर्षवर्धन सपकाल और वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात ने उन्हें बधाई दी।

एसबीआई सिक्योरिटीज ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में डिजिटल-फर्स्ट निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक की समूह कंपनी एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2025 में सक्रिय भागीदारी निभाई। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित इस तीन-दिवसीय कार्यक्रम में कंपनी ने अपने अत्याधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे और नवाचारों को प्रदर्शित किया। इस दौरान कंपनी ने उपयोगकर्ता अनुभव और निवेश दक्षता बढ़ाने वाले नए समाधान पेश किए। प्रमुख नवाचारों में 'एन्हांस्ड ऐप डैशबोर्ड' शामिल है, जिसमें नया 'एक्सप्लोर' सेक्शन निवेशकों को ऐप में सहज नेविगेशन, स्टॉक्स की विस्तृत जानकारी और सोच-समझकर निवेश निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, उन्नत MTF (मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी) - ई-मार्जिन समाधान पेश किया गया, जो कुशल, नियमों के अनुरूप और तकनीकी आधारित मार्जिन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के मुख्य व्यवसाय अधिकारी सुरेश शुक्ला ने कहा, "ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वित्त के भविष्य को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। हमारी भागीदारी डिजिटल ब्रोकरेज क्षेत्र में अग्रणी बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह मंच वैश्विक नियामकों, नीति निर्माताओं, स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक साथ लाता है और हमें अपनी तकनीकी ताकत और AI-आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। हम हर भारतीय निवेशक के लिए विश्वसनीय डिजिटल-फर्स्ट पार्टनर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, ताकि धन सृजन को सरल, सुलभ और निर्बाध बनाया जा सके।"

मुंबई में 60 स्थानों पर होगा छठ महोत्सव का आयोजन: भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम

राष्ट्रीय स्वाभिमान। सुजीत मिश्रा

मुंबई। मुंबई में इस वर्ष छठ महोत्सव का आयोजन पहले से अधिक व्यापक स्तर पर किया जाएगा। भाजपा विधायक एवं मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि महानगरपालिका इस बार 60 स्थानों पर छठ महोत्सव का आयोजन करेगी। पिछले तीन वर्षों से मुंबई महानगरपालिका 40 जगहों पर यह पर्व आयोजित कर रही थी।

मुंबई मनपा मुख्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक

कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा और भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम के नेतृत्व में आज मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में आगामी छठ पूजा के आयोजन एवं व्यवस्थापन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुंबई शहर के विभिन्न छठ

पूजा आयोजन मंडलों के प्रतिनिधि, बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में छठ पर्व के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था और जनसुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता

अमित साटम ने कहा, "छठ महोत्सव की जगहों में बढ़ोतरी से श्रद्धालुओं की भीड़ किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होगी। इसलिए हमने निवेदन किया है कि इस बार 27 अक्टूबर को मुंबई महानगर क्षेत्र में 60 स्थानों पर छठ महोत्सव का आयोजन किया जाए। इसके साथ ही उन सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में चलित शौचालय और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।"

सुरक्षा और यातायात पर विशेष ध्यान

भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि सभी छठ स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की मांग की गई है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सभी छठ आयोजन संस्थाओं को ऑनलाइन अनुमति प्रणाली के तहत इजाजत दी जाए। जिन संस्थाओं को पिछले वर्ष अनुमति मिली थी, उन्हें आगामी 5 वर्षों के लिए स्थायी अनुमति देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मेट्रो और बेस्ट बस सेवाएं 27 अक्टूबर की रात पूरी रात चलाने का निवेदन किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को घर आने-जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

समर्पण और व्यवस्था का संगम

बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि छठ महोत्सव मुंबई की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। भाजपा के नेतृत्व में इस वर्ष यह पर्व और भी अधिक भव्यता व सुव्यवस्था के साथ मनाया जाएगा।

ठाणे मनपा जल विभाग में 140 ठेका कर्मचारियों का आर्थिक शोषण, विधायक संजय केलकर ने ठेकेदार को काली सूची में डालने की मांग की

ठाणे। ठाणे मनपा के जल विभाग में पिछले कई वर्षों से ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में विधायक संजय केलकर ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसे काली सूची में डालने की मांग की।

खोपट स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जल विभाग के लगभग 140 ठेका कर्मचारियों ने विधायक केलकर से मुलाकात की और अपने आर्थिक शोषण की शिकायत की। कर्मचारी पिछले चार वर्षों से मीटर रीडिंग और पानी के बिल बांटने जैसे कार्य कर रहे हैं, जबकि उन्हें न्यूनतम वेतन 32 हजार रुपये मिलने चाहिए था, लेकिन ठेकेदार केवल 12 हजार रुपये दे रहा है। संविदा इंजीनियरों को भी अनुबंध के अनुसार 40,000 रुपये मिलने चाहिए, जबकि उन्हें केवल 15-

17 हजार रुपये ही दिए जा रहे हैं। विधायक संजय केलकर ने कहा कि ठेकेदार इन कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। इसे रोकने के लिए उसे सबसे पहले काली सूची में डालना चाहिए और कर्मचारियों का छीना हुआ वेतन वापस दिलाना हमारी प्राथमिकता है। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से यह लूट पिछले चार वर्षों से जारी है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।"

कार्यक्रम में परिवहन सदस्य विकास पाटिल, युवा मोर्चा के सूरज दलवी, भाजपा ठाणे उपाध्यक्ष महेश कदम, राजेश गाडे समेत अन्य नेता उपस्थित थे। संजय केलकर ने यह भी कहा कि गरीब निवासियों को खतरनाक इमारतों से जबरन बेदखल किया जा रहा है, जो अधिकारियों, डेवलपर्स, राजनीतिक हलकों और स्थानीय गुंडों की मिलीभगत से हो रहा है। ऐसे कामों को रोकने और अधिकारियों के अवैध अधिकार खत्म करने के लिए वे सख्त कार्रवाई करेंगे।

फेम ने करवा चौथ पर शुरू किया नया अभियान, महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर

मुंबई। डाबर समूह के फ्यूरने स ब्रांड फेम ने करवा चौथ के अवसर पर नया अभियान लॉन्च किया, जो आधुनिक महिला के स्वतंत्र और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण को उजागर करता है। इस अभियान में हसल फेम रैपर अग्सी को शामिल किया गया है, जो रीति-रिवाजों को अपनी शर्तों पर अपनाने वाली महिलाओं की आवाज़ बनकर सामने आती हैं। फेम का यह अभियान केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय, आत्म-अभिव्यक्ति और नारीत्व को भी बढ़ावा देता है। डाबर इंडिया के स्किनकेयर मार्केटिंग हेड विराट खन्ना और डीजीएम जसलीन कोहली ने कहा कि अभियान महिलाओं की सशक्तता, आत्मविश्वास और उनकी अनोखी चमक का जश्न मनाता है।

शख्सियत

धर्म, समाज और कर्म का संगम ही जीवन का सच्चा अर्थ है: सौरभ सिंह

राष्ट्रीय स्वाभिमान। प्रेम चौबे

जब संस्कारों की जड़ें गहरी हों और कर्मभूमि पर सेवा का बीज बोया जाए, तब जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है।

ऐसे ही एक प्रेरक युवा हैं सौरभ सिंह, जिनकी सोच में आध्यात्मिकता की गहराई और कर्म में समाजसेवा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।

प्रश्न 1: सौरभ जी, अपने परिवार और प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए।

उत्तर:

मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहूं क्षेत्र के कोरा बीर गांव में वर्ष 1997 में हुआ। मेरे पिता श्री प्रभात सिंह 'बबलू' और माता श्रीमती पुष्पा सिंह ने बचपन से ही हमें सेवा, धर्म और संस्कार का मूल्य सिखाया।

प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में प्राप्त करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन और फार्मेसी की पढ़ाई अपनी कर्मभूमि वसई-विरार (महाराष्ट्र) में पूरी की।

मेरे पिता स्वयं एक समाजसेवी हैं — उन्होंने मानिकपुर क्षेत्र में समाजसेवा की जो परंपरा शुरू की, वही आज मेरी प्रेरणा है।

प्रश्न 2: आपके जीवन में आध्यात्मिकता की भूमिका क्या है?

उत्तर:

हमारा परिवार वसई तालुका की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित कांवड़ यात्रा का आयोजन करता है। यह यात्रा केवल भक्ति का नहीं, बल्कि

सेवा और अनुशासन का प्रतीक है। मुझे लगता है कि समाजसेवा तभी सार्थक होती है जब उसमें ईश्वर के प्रति आस्था और मानवता के प्रति करुणा जुड़ी हो।

भक्ति और सेवा — यही मेरे जीवन के दो आधार हैं।

प्रश्न 3: कोरोना काल में आपके परिवार की भूमिका को समाज ने बहुत सराहा, उस अनुभव को कैसे देखते हैं?

उत्तर:

कोविड-19 महामारी के समय स्थिति बहुत कठिन थी। लोग भय और असहायता में थे।

तब मेरे पिता ने मित्रों के सहयोग से जौनपुर जिले के लोगों की मदद के लिए दो विशेष ट्रेनें रवाना करवाने की पहल की।

वह पल मेरे जीवन का turning point था, मैंने समझा कि सेवा किसी पद या पहचान से नहीं, बल्कि संवेदना से शुरू होती है।

प्रश्न 4: आप राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीति को कैसे देखते हैं?

उत्तर:

मेरी दृष्टि में राजनीति केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाजसेवा का सबसे बड़ा मंच है।

मेरे राजनीतिक प्रेरणास्रोत महाराष्ट्र के पूर्व गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह जी हैं। उनसे मैंने सीखा कि राजनीति धर्म और नैतिकता के आधार पर चलनी चाहिए।

धर्म हमारे खून में है, इसलिए राजनीति को मैं धर्म की तरह ही सेवा का साधन मानता हूँ, न कि व्यक्तिगत लाभ का।

प्रश्न 5: युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या है?

उत्तर:

आज के युवा को यह समझना होगा कि आधुनिकता और संस्कार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

अगर हम अपने धर्म, संस्कृति और परिवार से जुड़कर समाज के लिए कार्य करें, तो यही सच्ची देशभक्ति है।

मैं मानता हूँ कि धर्म मनुष्य को जोड़ता है, और राजनीति अगर धर्म के साथ चले तो समाज को ऊँचाई देती है।

सौरभ सिंह की यह यात्रा यह दर्शाती है कि भक्ति और कर्म, परंपरा और आधुनिकता, समाज और आत्मा सबका संगम एक युवा मन में संभव है।

वे उस नई पीढ़ी का चेहरा हैं जो व्यवसाय में सफल होकर भी समाज से जुड़े रहना चाहती है, और जो राजनीति को सुधार और सेवा का माध्यम मानती है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई पर हमले के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस का आंदोलन

मुंबई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई पर न्यायालय में एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। इस हमले के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्ष झीनत शबरीन के नेतृत्व में मंत्रालय के पास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पुतले के पास आज तीव्र आंदोलन किया गया।

झीनत शबरीन ने कहा कि न्यायाधीश देश की न्यायव्यवस्था के प्रमुख हैं और उनके खिलाफ

न्यायालय में हमला संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। यह हमला करने वाला वकील मनुवादी मानसिकता का है और लगातार संविधान-विरोधी बयान दे रहा है। इस घटना के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मुंबई युवक कांग्रेस ने भी इसका तीव्र विरोध किया।

युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के पास डॉ. आंबेडकर के पुतले के पास आरएसएस के स्वयंसेवक के प्रतीकात्मक पुतले को जोड़ मारकर इस हमले का विरोध जताया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन पर मामले दर्ज किए गए। झीनत शबरीन ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।

मुंबई युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद झीनत शबरीन का मुंबई में भव्य स्वागत किया गया। विमानतल से रैली निकालकर उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज, कुपरेज में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पुतलों पर पुष्प अर्पित कर अभिवादन किया और उसके बाद आंदोलन में भाग लिया।

BITSoM लॉन्च करता ऑल इंडिया टेस्ट फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा

मुंबई। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (BITSoM) ने मसाई के सहयोग से ऑल इंडिया BITSoM टेस्ट फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स (TOP-2025) लॉन्च किया। यह देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षा छात्रों को बिजनेस और टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रोफेशनल कार्यक्रमों में आवेदन और कोर्स चयन के लिए पात्र बनाएगी। परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी और इसमें अंकों पर आधारित कोर्स चयन मॉडल लागू होगा।

इस टेस्ट के माध्यम से छात्र BITSoM के छह महीने के ऑनलाइन कार्यक्रमों में आवेदन कर सकेंगे, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिज़नेस एनालिटिक्स, फिनटेक और डिजिटल मार्केटिंग। सभी कार्यक्रमों में AI-आधारित टूल्स और डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमताओं पर जोर दिया गया है, ताकि छात्र तेजी से उभरते एआई सेक्टर की

मांगों के अनुरूप तैयार हों।

मसाई के को-फाउंडर एवं सीईओ प्रतीक शुक्ला ने कहा, "यह पहल भारत में गुणवत्ता-आधारित, एआई-सक्षम शिक्षा को जनसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया BITSoM टेस्ट छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर मूल्यांकन करता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई और करियर को डिजिटल अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के अनुरूप आकार दे सकें।"

मुंबई-गोवा राजमार्ग मार्च 2026 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद

मुंबई/सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र के बुनियादी ढाँचे को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, बहुप्रतीक्षित मुंबई-गोवा राजमार्ग लगभग पूरा होने वाला है और मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह चालू करने की उम्मीद है। पनवेल से सिंधुदुर्ग तक फैले इस उन्नत 466 किलोमीटर लंबे चार-लेन राजमार्ग से वित्तीय राजधानी मुंबई और तटीय राज्य गोवा के बीच यात्रा का समय वर्तमान 12-13 घंटे से घटाकर केवल छह घंटे हो जाएगा। राजमार्ग की चौड़ी और सुगम सड़क यात्रा न केवल आरामदायक बनाएगी, बल्कि दैनिक यात्रियों, लंबी दूरी के वाहन चालकों और पर्यटकों के लिए सुरक्षा और दक्षता भी बढ़ाएगी। इस राजमार्ग से रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के कई कस्बों और गाँवों को भी जोड़ा जाएगा। बेहतर पहुँच से स्थानीय समुदायों, आतिथ्य व्यवसायों और परिवहन एवं रसद पर निर्भर उद्योगों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। राजमार्ग

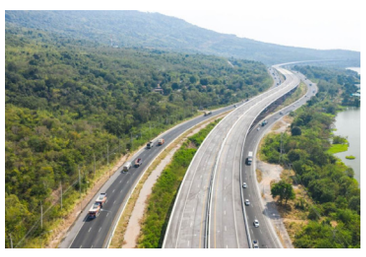

की एक और खासियत इसकी टोल संग्रह प्रणाली है, जो उपग्रह ट्रैकिंग और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) तकनीक पर आधारित होगी। इस प्रणाली से वाहनों को रुके बिना ही टोल कटौती संभव होगी, जिससे यातायात सुचारू रहेगा और समय व ईंधन की बचत भी होगी। यह परियोजना न केवल महाराष्ट्र के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यटन, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है।